गेहूं तथा चावल की नई किस्म

7806. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गेहूं तथा चावल की कौन-कौन सी किस्में निकाली गई हैं ;

(ख) उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) किस्मों का परीक्षण किन-किन कृषि फार्मों में किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं की नई विकसित की गई अधिक उपज देने वाली किस्मों के नाम और उनकी विशेषतायें नीचे दी गई हैं :—

किस्म	पकने के दिन	अनाज की किस्म	अनुकूलनशीलता
चावल की किस्में			
बाला	90–100	मोटा	वर्षा सिंचित ऊंची भूमि
कावेरी	90–100	मध्यम मोटा	बहु फसली रोपण
कांची	110–120	मोटा	बहु-फसली खेती
करुणा	110–120	मोटा	बहु-फसली खेती (तमिलनाडु, कुरुबाई मौसम)
अन्नपूर्णा	110–120	मोटा	प्रथम फसल, केरल
रत्ना	110–120	बढ़िया	पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब
कृष्णा	110–120	बढ़िया	बहु-फसली खेती
साबरमती	110–120	बढ़िया	उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
जमना	110–120	बढ़िया	उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
आई० आर० 20	120–130	बढ़िया	पूर्वी भारत
विजया	130–140	बढ़िया	साधारण खेती
गेहूं की किस्में			
हीरा	130–140	प्रवीतारक्त	सिंचित, उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
ए–9–30–1		प्रवीतारक्त	वर्षा से सिंचित, केन्द्रीय क्षेत्र
नर्बदा–4		प्रवीतारक्त	वर्षा से सिंचित, केन्द्रीय क्षेत्र

(ग) अखिल भारतीय समन्वित चावल विकास परियोजना के अन्तर्गत 24 मुख्य केन्द्र हैं। ये केन्द्र हैं—कोयम्बटूर, अदथुराय, पट्टाम्बी, मारुतेरु, हैदराबाद , मांड्या, रायपुर, कटक, भुवनेश्वर, चिंशराह, बर्दवान, पटना, जोरहाट, बेंगबाल, अगरतल्ला, फैंजाबाद, नगीना, लुधियाना, जोगेन्द्र नगर, करनाल, नवगांव, कारजात, अन्ततनाग, और कोटा। इसके अन्तर्गत लगभग 80 उपकेन्द्र भी हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय समन्वित गेहूं विकास परियोजना के अन्तर्गत 18 केन्द्र हैं। ये केन्द्र हैं :—भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली, भीवाली, पूसा, इन्दौर, विलिंगटन, लाहौल, घाटी, निफद, लुधियाना, पंतनगर, पीवार खेदा, दुर्गापुरा कानपुर बीजापुर पटना कल्याणी, रुद्रेउ, धारवार, और महाबलेश्वर। चावल और गेहू की कथित अधिक उत्पादनशील किस्मों का इन परियोजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रों में गहन परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके सर्वोत्तम अनुकूल क्षेंत्रों में (जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है) खेती के लिये निमुंक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, इन किस्मों क विभिन्न राजकीय फार्मों और राज्यों के क्षेंत्रीय अनुसन्धान केन्द्रों में भी सम्बन्धित कृषि विभागों द्वारा परीक्षण किया गया है।

Unutilize Funds for Social Welfare Schemes

7807. **DR. H. P. SHARMA:**
SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Times of India' dated the 30th March, 1973 under the caption 'Funds for Social Welfare Schemes unutilised; and

(b) if so, in which circumstances the social welfare schemes formulated under the 'Garibi Hatao' programme under reference failed to get off the ground during the year and the reasons why the allocations were allowed to lapse?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) It is true that in respect of certain social welfare schemes, there was non-utilisation or under-utilisation of funds. The non-utilisation or under utilisation has to be appreciated against the background of difficulties which beset the planning and implementation of social welfare schemes. The schemes are executed by the State Governments and a variety of voluntary organisations. The scheme are characterised by diversity not only as to their size but also the detailed circumstances attending a particular situation. There are also difficulties due to the inaccessibility of areas, particularly the hilly areas, which slow down the pace of implementation. In the face of these conditions, a good deal of time and labour has to be spent in fashioning the individual pattern of schemes as would best suit a particular case. There is also the factor of capacity of State Governments and the voluntary organisations to implement schemes. Conditions of social distress continue to change and, therefore, the measures to be employed to meet a situation have to be assessed through the means of through data and research. Time is therefore, of the essence to give final shape to schemes to ensure that these would most economically bring full and precise benefit to alleviate social ills.